नेताओं का पोर्टल; ऑनलाइन करेंगे शिकायत, खुद ट्रेक भी कर सकेंगे

राजकेड टीम के 3 युवाओं ने बनाया पोर्टल, नाम रखा- पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स एक्नालेजमेंट पोर्टल

नोडल विभाग वॉर रूम से मॉनिटरिंग करेगा

पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेटर्स एक्नालेजमेंट पोर्टल से 21 हजार सरपंच से लेकर सांसदों को जोड़ने के लिए हर एक ही ऑनलाइन प्रोफाइल आईडी प्रशासनिक सुधार विभाग बनाएगा। फिर हर प्रोफाइल के वेरिफाई होने पर उन्हें पोर्टल से जोड़ा जाएगा। उनसे सीधे डिपार्टमेंट के अफसरों को भी इसी तरह जोड़ा जाएगा। नोडल विभाग हर शिकायत की ऑनलाइन वार रूम से मॉनिटरिंग करेगा।

शिकायती पत्रों का लगता रहा है ढेर, अब 7 दिन के भीतर मिलेगा जवाब

▪ 11304 सरपंचों द्वारा साल में सीएम-मंत्री और विभाग को पत्र-	2.26 से 2.70 लाख
▪ 8,692 पार्षदों द्वारा साल में लिखे जाने वाले पत्र-	करीब 18 हजार
▪ 213 मेयर, सभापति, पालिकाध्यक्ष द्वारा लिखे पत्र-	लगभग 2,500
▪ पंचायत प्रधानों, जिला प्रमुखों द्वारा लिखे जाने वाले पत्र-	करीब 3 हजार
▪ 167 विधायकों या मंत्रियों द्वारा लिखे जाने वाले पत्र-	लगभग 4,000
▪ 35 लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के पत्र-	करीब 350

सरपंच भी देख सकेंगे अपनी फाइल का मूवमेंट

पोर्टल की खासियत यह होगी कि सरपंच से लेकर कोई भी नेता अपनी शिकायत की कॉपी का ऑनलाइन मूवमेंट देख सकेंगे। वे खुद बता सकेंगे कि किस अफसर ने फाइल रोकी। सात दिन में अफसर ने जवाब नहीं दिया तो पोर्टल टीम से रिमाइंडर जाएगा कि उनसे जुड़े काम का निस्तारण नहीं हुआ है। पेंडेंसी रखने वाले अफसरों की रिपोर्ट सीएम तक जाएगी।

हमारे सरपंच ब्लाक, जिला, संभाग स्तर पर तो सालाना 100 से ज्यादा पत्र लिखते हैं। इससे ऊपर मंत्री, सीएम और विभागों को भी औसतन 20 से 25 पत्र हर साल लिखते हैं। सरपंच के पास कई काम दिए जाते हैं, लेकिन सरपंचों को दिक्कत आती है, तब सुनवाई की जगह बड़े नेता राजनीति कर देते हैं। इसलिए पत्र लिखने पड़ते हैं। मैं ही 200 से अधिक पत्र हर साल लिखता हूं।

-रफीक पठान, प्रदेश प्रवक्ता, सरपंच संघ राजस्थान

हमारे पत्रों से काम नहीं हुआ तो जब सीएम जोधपुर आए तब सीधे मिलकर 3 बार ज्ञापन दिए, तब उन्होंने जनता जल योजना के पैंडिंग काम करवाए।

-अचल सिंह गहलोत, अध्यक्ष, सरपंच संघ तिंवरी